

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० १५५]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त २९, १९७०/भाद्र ७, १८९२

No. 155]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 29, 1970/BHADRA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August 1970

**G.S.R. 1266.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 1 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ministers' Allowances, Medical Treatment and other privileges) Rules, 1957, namely:—

1. These rules may be called the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other privileges) Amendment Rules, 1970.

2. In rule 3 of the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other privileges) Rules, 1957, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely:—

“(3) There shall be granted to—

(a) the Minister of Supply, Minister of Foreign Trade and Minister of Company Affairs, with effect from the 27th June, 1970, a sumptuary allowance of Rs. 250 per mensem;

(b) the Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs, with effect from 1st July, 1970, a sumptuary allowance of Rs. 250 per mensem”.

[No. 14/29/70-Pub.I.]

## Memorandum

Sumptuary allowance given to Ministers who are not members of the Cabinet, is determined in each case having regard to the requirements of the particular assignment of the Minister. Formulation and consideration of proposals in this behalf takes time and the amendment of the rules in such cases has necessarily to be given retrospective effect. No one's interest is prejudicially affected by reason of retrospective effect, as is being given in this Notification.

K. R. PRABHU, Jt Secy.

## गृह मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली 29 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1266.—मंत्रियों के संबन्धों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1 ये नियम मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1970, कहे जा सकेंगे।

2 मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957, में उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(3) (क) पूर्ति मंत्री, विदेश व्यापार मंत्री और कम्पनी कार्य मंत्री को 27 जून, 1970 से 250.00 रु० प्रतिमास का संचुअरी भत्ता ;

(ख) संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री को, 1 जुलाई 1970 से, 250.00 रु० प्रतिमास का संचुअरी भत्ता ;

अनुदत्त किया जाएगा।”

[संख्या 14/29/70-पब1]

## ज्ञापन

उन मंत्रियों को जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हैं, दिया गया संचुअरी भत्ता, प्रत्येक मामले में, मंत्री को विशिष्ट रूप से सौंपे गए कार्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर अवधारित किया जाता है। इस निमित्त प्रस्तावों को बनाने और उन पर विचार करने में समय लगता है और ऐसे मामलों में नियमों के संशोधन को आवश्यक रूप से भूतलक्षी प्रभाव देना होता है। इस भूतलक्षी प्रभाव से जैसा कि हम अधिसूचना को दिया जा रहा है, किसी के भी हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

के० आर० प्रभु, संयुक्त सचिव।